उत्तर प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष महाना देवनानी से मिले

देवनानी ने उन्हें राजस्थान विधानसभा सदन, भवन, संग्रहालय और कांस्टीट्यूशन क्लब का अवलोकन कराया

■ यूपी स्पीकर सतीश महाना ने राजस्थान विधानसभा भवन की अनूठी स्थापत्य संरचना, ऑनलाइन व पेपरलैस कार्यप्रणाली की प्रशंसा की।

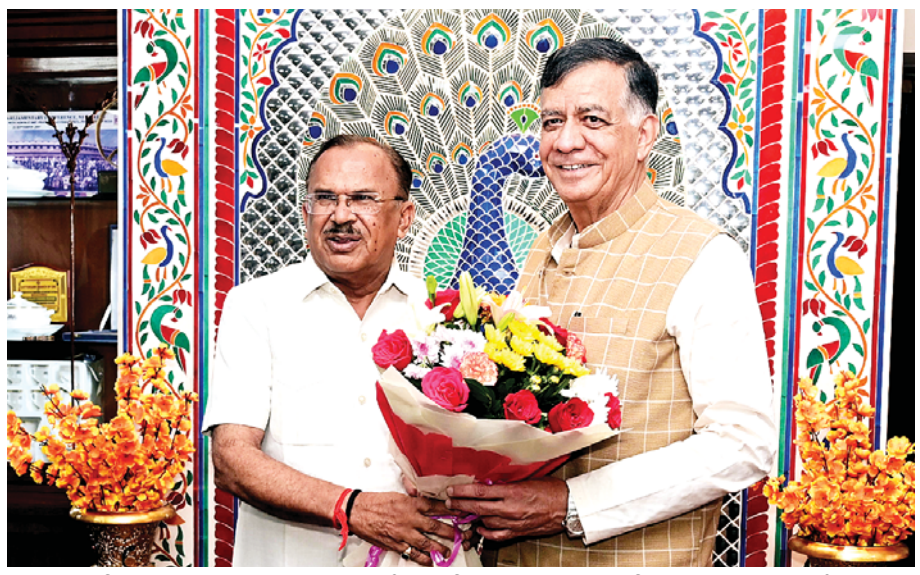

राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी से शनिवार को उत्तर प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने शिष्टाचार भेंट की। इस अवसर पर संसदीय कार्यप्रणाली, लोकतांत्रिक परंपराओं, विधायिका की चुनौतियां और उसकी प्रभावी भूमिका पर चर्चा की।

जयपुर,16 अगस्त। राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी से शनिवार को यहां विधानसभा में उत्तर प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने शिष्टाचार भेंट की। दोनों अध्यक्षों ने संसदीय कार्यप्रणाली, लोकतांत्रिक परंपराओं, विधायिका की चुनौतियां और उसकी प्रभावी भूमिका पर चर्चा की।

देवनानी ने राजस्थान विधानसभा की विशेषताओं, नवाचारों , सदन की ऑनलाइन एवं पेपरलेस प्रक्रिया, पारदर्शी कार्यशैली की जानकारी दी। महाना ने राजस्थान विधानसभा भवन की अनूठी स्थापत्य संरचना, सदन की ऑनलाइन एवं पेपरलेस कार्यप्रणाली और यहां विकसित की गई आधुनिक व्यवस्थाओं से संबंधित विभिन्न नवाचारो का अवलोकन किया। उन्होंने विधानसभा संग्रहालय (म्यूज़ियम) का भी दौरा किया और वहाँ प्रदर्शित संसदीय धरोहर, संविधानिक इतिहास एवं राजस्थान की समृद्ध लोकतांत्रिक परंपरा से संबंधित दुर्लभ दस्तावेज़ों की सराहना की।

देवनानी ने महाना को बताया कि राजस्थान विधानसभा में भारतीय नव वर्ष के अनुसार वार्षिक डायरी का प्रकाशन किया गया है। विधानसभा में कारगिल शौर्य वाटिका का निर्माण किया गया है। विधानसभा के राजनीतिक आख्यान संग्रहालय में राजस्थान के महापुरुषों और विभिन्न क्रांतियों से संबंधित जानकारियों तथा संवैधानिक दीर्घा के नवाचार भी समावेशित किये गये हैं। देवनानी ने महान को क्लब का अवलोकन करते हुए बताया कि क्लब के विभिन्न सभागारों का नामकरण भारतीय शब्दों पर किया गया है। देवनानी ने महाना को पुष्प गुच्छ व स्मृति चिन्ह भेंट कर तथा दुपट्टा व शाल ओढ़ ाकर सम्मानित किया तथा देवनानी ने महाना के सम्मान में उन्हें दोपहर भोज भी दिया।

घर-घर जाकर मतदाता सूची जांचेगी कांग्रेस

नयी दिल्ली, 16 अगस्त। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के चुनाव आयोग पर मतदाता सूचियों में गड़बड़ियों के आरोप को लेकर देशभर में अभियान चलाने की पार्टी की घोषणा के बीच युवा कांग्रेस ने घर-घर जाकर मतदाताओं का सूची से मिलान करने का अभियान शुरू किया।

युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानु चिब ने शनिवार को एक बयान में कहा कि उन्होंने जम्मू (उत्तर)

■ युवा कांग्रेस ने मतदाता सूचियों में कथित गड़बड़ी के कारण यह निर्णय लिया है।

विधानसभा में कार्यकर्ताओं के साथ तथाकथित वोट चोरी के खिलाफ घर-घर मतदाताओं से संपर्क कर इस अभियान की शुरुआत की। चिब ने कहा, लोकतंत्र की लड़ाई अब हर बूथ तक पहुँच चुकी है। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के आव्हान पर वोट चोरी रोको आंदोलन का एलान किया गया है। मैंने जम्मू (उत्तर) विधानसभा क्षेत्र में अपने बूथ की सूचियों से जुड़े मतदाताओं से घर-घर जाकर नामों की पुष्टि शुरू की ।

अब देश आत्म ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

इस अवसर पर संसदीय कार्यमंत्री जोगाराम पटेल, राज्य किसान आयोग के अध्यक्ष सी. आर. चौधरी, अमृता देवी राज्य जीव जंतु कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष जसवंत बिश्नोई सहित, अन्य गणमान्यजन एवं बड़ी संख्या में आमजन उपस्थित थे।

एनडीए संसदीय दल की बैठक मंगलवार को आहूत

बैठक में उपराष्ट्रपति पद के लिए भाजपा द्वारा सुझाए गए प्रत्याशियों के नामों पर चर्चा होगी

नयी दिल्ली, 16 अगस्त। सत्तारूढ़ राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) के संसदीय दल की बैठक मंगलवार को बुलायी गयी है, जिसमें उप राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की ओर से सुझाये गये नाम का अनुमोदन किया जा सकता है।

भाजपा के एक पदाधिकारी ने बताया कि राजग संसदीय दल की बैठक 19 अगस्त को पूर्वाह्न 9:30 बजे बुलायी गयी है, जिसमें सभी घटक दलों के सदस्य और कुछ बड़े नेता मौजूद रहेंगे। संसद के इस मानसून सत्र में राजग संसदीय बोर्ड की यह दूसरी बैठक है। इससे पहले पांच अगस्त को राजग संसदीय बोर्ड की संसद के वर्तमान सत्र में हुई पहली बैठक में ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का अभिनंदन किया गया था। उसी बैठक में तय हुआ था कि उप राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के नाम की सिफारिश भाजपा अध्यक्ष जे पी नड्डा और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह करेंगे।

राजग की इस बैठक से पहले यहां भाजपा संसदीय बोर्ड की एक बैठक रविवार शाम को होगी। इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, भाजपा अध्यक्ष जे पी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ संगठन महासचिव बी एल संतोष समेत पार्टी के वरिष्ठ नेता शामिल होंगे।

सूत्रों के अनुसार, कल होने वाली

■ इससे पहले रविवार शाम को भाजपा संसदीय दल की बैठक होगी, जिसमें प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा सहित पार्टी के कई वरिष्ठ नेता भाग लेंगे।

इस बैठक में अन्य महत्वपूर्ण राजनीतिक मुद्दों के अलावा उप राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार का नाम तय किए जाने की संभावना है। भाजपा संसदीय बोर्ड नड्डा और सिंह की सिफारिश के आधार पर उपराष्ट्रपति पद के लिए प्रत्याशी तय कर सकता है।

भाजपा अध्यक्ष नड्डा के आवास पर शुक्रवार को एक बैठक हुई थी। इसमें राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा के कुछ अन्य वरिष्ठ नेता मौजूद थे। सूत्रों के अनुसार राजग गठबंधन के सहयोगी दल भाजपा संसदीय बोर्ड में तय उम्मीदवार का समर्थन करेंगे।

सूत्रों के अनुसार, भाजपा ने राजग गठबंधन शासित राज्यों के सभी मुख्यमंत्रियों और उप मुख्यमंत्रियों को उप राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के नामांकन पत्र दाखिल करने के दिन, 21 अगस्त को दिल्ली में रहने को कहा है। बीस अगस्त को राजग का रात्रिभोज कार्यक्रम आयोजित होने की भी संभावना है। उप राष्ट्रपति पद के लिए नामांकन की अंतिम तिथि 21 अगस्त है और आवश्यता हुई तो मतदान नौ सितंबर को कराया जाएगा। इस चुनाव में राज्य सभा के सभी सदस्यों और लोक सभा के सभी गैर नामित सदस्य मतदाता होते हैं। भाजपा ने राज्य सभा और लोक सभा दोनों के अपने सांसदों को छह से नौ सितंबर तक अनिवार्य रूप से राजधानी में रहने का निर्देश दिया है। इस दौरान वे भाजपा मुख्यालय में उप राष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान प्रक्रिया पर होने वाली कार्यशाला में भाग लेंगे।

भजनलाल ने ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

राजस्थान के लिए मिलकर कार्य करना होगा। इसके पश्चात शर्मा ने जयनिवास बाग में ही देवस्थान विभाग के राजकीय प्रत्यक्ष प्रभार श्रेणी के मंदिर श्री लक्ष्मीनारायण जी में भी दर्शन किए। मुख्यमंत्री ने गोविन्द देव जी मंदिर परिसर में बड़ी संख्या में मौजूद श्रद्धालुओं का अभिवादन स्वीकार किया। इस अवसर पर विधायक बालमुकुन्दाचार्य सहित, विशिष्ट गणमान्यजन उपस्थित थे।

कांग्रेस ने कहा, बंटवारे के दोषी हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग

कांग्रेस ने एनसीईआरटी के मॉड्यूल को खारिज किया जिसमें कांग्रेस को बंटवारे का दोषी ठहराया था

■ कांग्रेस संचार विभाग के प्रमुख पवन खेड़ा ने कई उदाहरण दिए अपनी बात की पुष्टि के लिए।

■ खेड़ा ने कहा 1938 में हिंदू महासभा ने अपने अधिवेशन में प्रस्ताव पारित किया था कि हिंदू मुसलमान साथ नहीं रह सकते और 1940 में मुस्लिम लीग ने भी यही प्रस्ताव पारित किया था, एनसीईआरटी मॉड्यूल में इन दोनों बातों का जिक्र नहीं है।

■ खेड़ा ने कहा, 1942 में हिंदू महासभा व मुस्लिम लीग ने सिंध, बंगाल, उत्तरपश्चिम सीमा प्रांत में गठबंधन सरकार बनाई और विधानसभा में विभाजन का प्रस्ताव पारित करवाया, जबकि कांग्रेस तब सभी प्रांतीय विधानसभाओं से इस्तीफा देकर भारत छोड़ो आंदोलन कर रही थी, एनसीईआरटी के मॉड्यूल में इस तथ्य का जिक्र भी नहीं है।

नयी दिल्ली, 16 अगस्त। कांग्रेस पार्टी ने देश विभाजन के बारे में राष्ट्रीय शिक्षा अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (एनसीईआरटी) द्वारा प्रकाशित 'विभाजन के दोषी' शीर्षक मॉडयूल पर सवाल उठाते हुए कहा है कि देश के बंटवारे के लिए हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग की 'जुगलबंदी' जिम्मेदार है और इतिहास का सबसे बड़ा खलनायक राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ (आरएसएस) है।

कांग्रेस संचार विभाग के प्रमुख पवन खेड़ा ने संवाददाता सम्मेलन में एनसीईआरटी के 14 अगस्त को जारी उस मॉड्यूल पर कहा, ' इसमें 1938 की तारीख का जिक्र है या नहीं है। बंटवारे के इतिहास में 1938 बहुत महत्वपूर्ण तारीख है। इस वर्ष गुजरात में साबरमती के किनारे हिंदू महासभा का राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ था, जिसमें ये स्पष्ट तौर से कहा गया था कि हिंदू और मुसलमान एक देश में नहीं रह सकते। उन्होंने कहा, " 1940, क्या यह है मॉड्यूल में। 1940 में इस जुगलबंदी को आगे बढ़ ते हुए मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में जिन्ना ने यही बात दोहरायी थी।

खेड़ा ने कहा, मैं दावे के साथ कह सकता हूं, (इसमें) 1942 की भी ये तारीख भी नहीं लिखी होगी, जब हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग की मिलीजुली सरकार बनी थी। उस समय कांग्रेस ने तमाम प्रांतीय विधानसभाओं से इस्तीफा देकर सड़क पर उतरने के लिए भारत छोड़ो आंदोलन का आ ान किया था। उस वक्त हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग ने गठजोड़ किया, गठबंधन किया, सरकारें बनाई एनडब्ल्यूएफपी में, बंगाल में, सिंध में और सिंध की विधानसभा में विभाजन का प्रस्ताव पारित हुआ था।

कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा, उस समय हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग के गठबंधन की सरकार थी। उन्होंने पूछा कि एनसीईआरटी ने क्या उस मॉड्यूल में यह सब लिखा है? अगर नहीं लिखा है तो आग लगा दीजिए इस किताब को। ये है हकीकत। ये हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग की जुगलबंदी से बंटवारा हुआ है। उन्होंने कहा, इतिहास का अगर सबसे बड़ा विलेन कोई है, तो राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ है। पीढ़ि यां उनको माफ नहीं करेंगी जो उनका योगदान रहा है।

राष्ट्रपति मुर्मू ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

मुर्मु और मोदी तथा अनेक केन्द्रीय मंत्री सुबह 'सदैव अटल' पहुंचे और दिवंगत नेता को श्रद्धांजलि अर्पित करने के बाद वहां आयोजित प्रार्थना सभा में शामिल हुए।

लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केन्द्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा, किरण रिजिजू, गजेंद्र सिंह शेखावत तथा जदयू सांसद संजय झा और दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और अनेक गणमान्य व्यक्तियों ने पूर्व प्रधानमंत्री वाजपेयी को श्रद्धांजलि अर्पित की।

मोदी ने वाजपेयी को भारत के विकास और आत्मनिर्भरता की यात्रा का मार्गदर्शक बताया। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्ट में कहा, अटल जी को उनकी पुण्यतिथि पर स्मरण। भारत की सर्वांगीण प्रगति के प्रति उनका समर्पण और सेवा भावना सभी को एक विकसित और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण के लिए प्रेरित करती रहेगी।

राष्ट्रपति और राज्यपालों के लिए समय सीमा तय करने पर केन्द्र की चेतावनी

केन्द्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल जवाब में कहा कि इससे संवैधानिक अराजकता पैदा होगी

■ केन्द्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा अप्रैल में दिए गए एक निर्देश के जवाब में यह टिप्पणी की। सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया था कि राष्ट्रपति व राज्यपाल राज्य विधानसभाओं के विधेयकों पर तीन माह के भीतर फैसला करें।

नई दिल्ली, 16 अगस्त। सरकार ने राष्ट्रपति और राज्यपालों पर विधेयकों को मंजूरी देने के लिए समय-सीमा थोपने के खिलाफ चेतावनी दी है। केंद्र सरकार ने चेताया कि इससे देश में सांविधानिक अराजकता पैदा हो सकती है। न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति आर महादेवन की पीठ ने अप्रैल में अपने एक निर्देश में विधेयकों को मंजूरी के लिए राष्ट्रपति के लिए तीन महीने और राज्यपालों के लिए एक महीने की समय-सीमा निर्धारित की थी ताकि विधायिका द्वारा पारित विधेयकों पर निर्णय हो सके।

केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल एक लिखित निवेदन में कहा कि ऐसी समय-सीमाएं तय करना ऐसा है, जैसा सरकार के किसी अंग द्वारा उन शक्तियों का हड़पना, जो उसमें निहित नहीं हैं। इससे संविधान में उल्लेखित शक्तियों का पृथक्करण बिगड़ सकता है। सरकार ने चेतावनी दी कि इससे सांविधानिक अराजकता पैदा होगी। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अपने निवेदन में कहा, अनुच्छेद 142 में निहित अपनी असाधारण शक्तियों के बावजूद भी, सुप्रीम कोर्ट संविधान में संशोधन नहीं कर सकता या संविधान निर्माताओं की मंशा को विफल नहीं कर सकता।

राज्यपाल के खिलाफ तमिलनाडु सरकार की याचिका पर दिए गए अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने सलाह दी कि राष्ट्रपति को तीन महीने के भीतर राज्यपालों द्वारा भेजे गए लंबित विधेयकों पर फैसला ले लेना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने 8 अप्रैल दिए फैसले में सुझाव देते हुए कहा कि हम ये सलाह देते हैं कि राष्ट्रपति को राज्यपाल द्वारा उनके विचार के लिए भेजे गए विधेयकों पर तीन महीने के भीतर फैसला लेना जरूरी है। पीठ ने कहा कि इस समयसीमा से ज्यादा की देरी होने पर उचित कारण देने होंगे और इस बारे में संबंधित राज्य को सूचित करना होगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सुप्रीम कोर्ट से 14 सवाल किए थे। इस पर काफी विवाद हुआ था।

ओबामा, बाइडन व ट्रम्प चाहते थे, कि भारत, ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

ऑस्ट्रेलिया पूरी तरह से अमेरिकी सुरक्षा गारंटी पर निर्भर हैं। अमेरिका ने भारत की टकराव की इच्छा को गलत आंका, यह भूलकर कि चीन से सीधा संघर्ष भारत के लिए लंबे समय तक भारी आर्थिक और सुरक्षा व्यय ला सकता है। यही अंतर, किसी एक नीति से ज़्यादा, आज के तनाव की असली वजह है।

फिर भी यह कहना गलत होगा कि रिश्ते पूरी तरह टूट रहे हैं। यह एक "रीसैट" जैसा है। दोनों देशों के बीच व्यापार, तकनीक साझेदारी, रक्षा सौदे और भारतीय प्रवासी समुदाय के मजबूत रिश्ते अभी भी मौजूद हैं। लेकिन रणनीतिक मुद्दों पर भरोसे की कमी बढ़ रही है और कभी प्राकृतिक गठबंधन कहे जाने वाले रिश्ते में अब खिंचाव साफ दिख रहा है।

भारत के लिए चुनौती है कि वह वॉशिंगटन और बीजिंग के बीच किसी एक को चुनने की सुविधा से एकदम दूर रहे। अमेरिका की तरफ ज़्यादा झुकाव चीन के साथ टकराव ला सकता है, जो भारत नहीं चाहता, वहीं अमेरिका से दूरी पश्चिमी पूंजी, तकनीक और रक्षा ज्ञान से वंचित कर सकती है, जिसकी भारत को आधुनिकीकरण के लिए ज़रूरत है। इसलिए मध्य मार्ग - रक्षा में आत्मनिर्भरता, आर्थिक मजबूती और मल्टी, अलाइनमैंट, यानी कई देशों से संतुलित रिश्ते ही टिकाऊ विकल्प हैं।

इस नज़रिये से, यह कहना कि रिश्ते 20 सालों में सबसे निचले स्तर पर हैं, कुछ बढ़ा-चढ़ा कर कहना होगा, लेकिन दिशा साफ है। अमेरिका ने कभी सच में बराबरी की साझेदारी नहीं चाही; उसने भारत को चीन के खिलाफ एक रणनीतिक संतुलनकर्ता के रूप में देखना चाहा। भारत द्वारा इस भूमिका को ठुकराने से ही आज की खाई बनी है। ट्रंप के ऊँचे शुल्क और पाकिस्तान की तरफ झुकाव ने इसे और चौड़ा किया है। आगे का रास्ता इस पर निर्भर करेगा कि भारत अपनी स्वायत्तता को मज़बूत रखते हुए वॉशिंगटन और बीजिंग, दोनों से अपने विकास और सुरक्षा के लिए लाभ ले सकेगा या नहीं।

नाहरगढ़ की...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

पास पहाड़ी पर सुबह घूमने पहुंचे युवकों ने खाई में नर कंकाल होने की जानकारी पुलिस को दी। इस पर पुलिस टीम को मौके पर भेजकर चेक किया गया। इसके बाद सिविल डिफेंस और एफएसएल की टीम को भी जानकारी दी गई। इसके बाद मौके से नर कंकाल को बरामद कर सबूत जुटाए जा रहे हैं।

शेखावत ने बताया कि कंकाल के कपड़ों से पहचान की जा रही है। इसमें पेंट, शर्ट, नए जूते के आधार पर पहचान का प्रयास किया जा रहा है। इसके अलावा, नर कंकाल का सत्तर प्रतिशत मांस जंगली जानवर खा चुके थे। मौके पर सिर्फ खोपड़ी, दांत, पैर-हाथ की हड्डियां, जींस, शर्ट और जूते मिले हैं। डॉक्टरों की टीम ने नर कंकाल की जांच करने के बाद उसे मोर्चरी में रखवा दिया गया है। पुलिस के अनुसार, अगर मृतक किसी के साथ पहाड़ी पर गया था तो साथ वालों ने पुलिस को गुमशुदा होने की जानकारी दी होगी। इसी को लेकर नाहरगढ़ और ब्रह्मपुरी थाना पुलिस इस पर काम कर रही है।

बड़ी उत्कंठा से ट्रम्प-पुतिन मीटिंग का इन्तज़ार ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

■ दूसरी ओर ट्रम्प ने, पुतिन के लिए अरबों डॉलर का आकर्षक आर्थिक तोहफा तैयार किया है, जिसमें रूस की खनिज सम्पदा का दोहन व अन्य सौगातें शामिल हैं। पुतिन इन तोहफों पर बातचीत करने के लिए उद्योगपतियों व बिजनेस वाले लोगों का एक प्रतिनिधि मण्डल भी लाये हैं, पर इन पर वार्ता तभी होगी जब पुतिन का यूक्रेन के बारे में प्रस्ताव स्वीकार हो जाता है।

पुतिन ने पहले भी कई बार पूर्व सोवियत संघ (यू. एस. एस. आर.) के दौर को स्वर्ण काल बताया है, जब रूस अपने अधीन आने वाले गणराज्यों पर शासन करता था। उस समय यूक्रेन भी एक सोवियत गणराज्य था और सोवियत संघ का अभिन्न अंग था। यही वह "साम्राज्यवादी रूस" है, जिसे व्लादिमीर पुतिन दोबारा स्थापित करना चाहते है।

यह न केवल यूक्रेन के लिए, बल्कि कज़ाख़िस्तान, उज्बेकिस्तान और अन्य मध्य एशियाई देशों के लिए भी चिंता की बात होनी चाहिए, जो अब सोवियत संघ से स्वतंत्र हैं। हालांकि, यह मान लेना गलत होगा कि रूस इन सभी देशों को फिर से अपने अधीन लाने की कोशिश नहीं करेगा।

पुतिन पहले ही कह चुके हैं कि पूर्व सोवियत संघ का विघटन "20वीं सदी की सबसे बड़ी भू-राजनीतिक त्रासदी" थी, जिसे वे किसी न किसी रूप में पुनर्स्थापित करना चाहते हैं। पश्चिमी मीडिया ने इस रूसी रवैये की तुलना ट्रंप की "मेक अमेरिका ग्रेट अगेन" नीति से करते हुए, इसे "मेक रशिया ग्रेट अगेन" करार दिया है।

ऐसे मानसिकता में यह कल्पना करना मुश्किल है कि अलास्का में ट्रंप-पुतिन वार्ता यूक्रेन की संप्रभुता का सम्मान करते हुए कोई निष्पक्ष समाधान निकाल पाएगी। रूस का पूरा रुख, यूक्रेन की ज़मीन का अधिक से अधिक हिस्सा हड़पने के एक मात्र ध्येय पर केन्द्रित दिखाई देता है। ज़मीनी स्तर पर रूस अब भी यूक्रेनी नागरिक ठिकानों पर हमले कर रहा है, ताकि आम लोगों में भय का माहौल पैदा हो सके।

फिर भी, एंकरेज बैठक आशा की एक किरण बनी हुई है, क्योंकि डॉनल्ड ट्रंप ने संकेत दिया है कि रूसी टीम अमेरिका के साथ आर्थिक समझौतों को लेकर उत्साहित है, और यह इस बात पर निर्भर करेगा कि रूस युद्ध के समाधान पर क्या रुख अपनाता है।

रूसी प्रतिनिधिमंडल एक मज़बूत टीम के साथ आया है, जिसमें व्यवसायी, वित्त मंत्री और प्रमुख आर्थिक वार्ताकार "किरिल दिमित्रिएव" शामिल हैं, जो सऊदी अरब सम्मेलन में भी रूस की ओर से वार्ता कर चुके हैं। दिमित्रिएव रूस के "सॉवरेन वेल्थ फंड (राष्ट्रीय संपत्ति कोष) के प्रमुख भी हैं।

ट्रंप रूस के लिए अरबों डॉलर की निवेश योजनाओं के रूप में एक आकर्षक आर्थिक पैकेज लेकर आए हैं। इसमें रूस के विशाल खनिज संसाधनों के विकास की योजनाएँ भी शामिल हैं। रूसी राष्ट्रपति भी इस बैठक में आर्थिक समझौतों को प्रमुख मुद्दा बनाकर आए हैं।

यह बैठक भारत के लिए भी महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सकती है, भले ही भारत इस पर बहुत अधिक केन्द्रित न हो। अगर एंकरेज वार्ता सफल रहती है, तो अमेरिका द्वारा लगाए गए सैकेण्डरी सैक्शन्स को हटाया जा सकता है, जो भारत के लिए भी फायदे की बात होगी।

यूट्यूबर ज्योति के खिलाफ चार्जशीट दाखिल

हिसार, 16 अगस्त। जासूसी के आरोप में गिरफ्तार यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा के खिलाफ हिसार पुलिस ने कोर्ट में चार्जशीट दायर की है। 2500 पेजों की चार्जशीट को 3 महीने की जांच के बाद दायर किया गया है। सूत्रों के मुताबिक ज्योति के खिलाफ पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के पक्के सबूत मिले हैं।

पुलिस ने चार्जशीट में बताया कि वो काफी लंबे समय से जासूसी कर रही थी। वो पाकिस्तानी एंबेसी के अधिकारी एहसान उर रहीम दानिश अली के लगातार संपर्क में थी। ज्योति आईएसआई एजेंट शाकिर, हसन अली और नासिर ढि ल्लो से बात करती थी।

मणिपुर के राज्यपाल को नागालैंड का भी प्रभार

नई दिल्ली, 16 अगस्त। मणिपुर के राज्यपाल अजय कुमार भल्ला को शनिवार को नागालैंड के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। यह पद नगालैंड के राज्यपाल ला गणेशन के निधन के बाद रिक्त हुआ था। 80 वर्षीय गणेशन का शुक्रवार को चेन्नई के एक निजी अस्पताल में इलाज के दौरान निधन हो गया था।

सरकार की ओर से जारी विज्ञिप्त में कहा गया है, नागालैंड के राज्यपाल ला गणेशन के निधन के उपरांत, भारत के राष्ट्रपति ने मणिपुर के राज्यपाल अजय कुमार भल्ला को नगालैंड के राज्यपाल के रूप में अपनी जिम्मेदारियों के साथ-साथ अतिरिक्त कार्यभार संभालने के लिए नियुक्त किया है।

आईएएस अधिकारी (सेवानिवृत्त) अजय कुमार भल्ला को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पिछले साल ही मणिपुर का राज्यपाल नियुक्त किया था। अजय कुमार भल्ला 1984 बैच के सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी हैं। अजय कुमार भल्ला को 22 अगस्त, 2019 को केन्द्रीय गृह सचिव नियुक्त किया गया था। उन्होंने 22 अगस्त 2024 तक लगभग पांच वर्षों तक भारत के गृह सचिव के रूप में कार्य किया।

वैश्विक राजनीति की मजबूरियां करीब ला रही हैं भारत और...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

विदेश मंत्री एस. जयशंकर भी अपने चीनी समकक्ष के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे।

पिछले साल दिसंबर में डोभाल चीन गए थे और वांग के साथ एसआर वार्ता की थी। इससे कुछ सप्ताह पूर्व, प्रधानमंत्री मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की रूस के कज़ान शहर में हुई बैठक के दौरान, विभिन्न संवाद तंत्रों को पुनर्जीवित करने का निर्णय लिया गया था।

प्रधानमंत्री मोदी के इसी महीने के अंत में चीन यात्रा पर जाने की संभावना है, जहाँ वे एससीओ शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे।

योजना के अनुसार, मोदी 29 अगस्त को जापान की यात्रा पर जाएंगे और फिर वहाँ से सीधे चीन के उत्तरी शहर तियानजिन रवाना होंगे, जहाँ 31 अगस्त और 1 सितंबर को शिखर सम्मेलन आयोजित होना है।

प्रधानमंत्री की यह चीन यात्रा दोनों पड़ोसी देशों के संबंधों के सुधार के प्रयासों के बीच हो रही है, जो जून 2020 में गलवान घाटी में भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच हुई घातक झड़पों के बाद गंभीर रूप से बुरी तरह प्रभावित हो गये थे।

मई 2020 में पूर्वी लद्दाख में सैन्य गतिरोध और जून में गलवान घाटी की झड़पों के परिणामस्वरुप द्विपक्षीय सम्बन्ध काफी तनावपूर्ण हो गये थे।

यह गतिरोध प्रभावी रूप से उस समय समाप्त हुआ था, जब 21 अक्टूबर 2024 को डेमचोक और डेपसांग से सेनाओं के पीछे हटने की प्रक्रिया पूरी हो गई थी।

मोदी और शी जिनपिंग के बीच 23 अक्टूबर 2024 को कज़ान में हुई बैठक में विभिन्न संवाद तंत्रों को फिर से शुरू करने का निर्णय लिया गया था।

यह बैठक उस समझौते के दो दिन बाद हुई थी, जिसमें भारत और चीन ने डेपसांग और डेमचोक से सेनाओं की वापसी सुनिश्चित हो गई थी।

दोनों देशों ने रिश्तों को सुधारने के लिए कई पहल की हैं, जैसे कैलाश मानसरोवर यात्रा की बहाली और भारत द्वारा चीनी नागरिकों को पर्यटक वीज़ा जारी करना शुरू किया जाना।

इसके अलावा, दोनों पक्षों के बीच सीधी उड़ान सेवाओं को फिर से शुरू करने के तौर-तरीकों पर भी चर्चा हो रही है।

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और एस. जयशंकर पिछले दो महीनों में एससीओ की बैठकों में भाग लेने के लिए चीन जा चुके हैं।

वर्तमान में चीन एससीओ का अध्यक्ष है।

इससे पहले गुरुवार को चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता लिन जिआन ने वांग की भारत यात्रा की अटकलों पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा, "हम भारत के साथ मिलकर, दोनों देशों के नेताओं के बीच बनी महत्वपूर्ण साझा समझ पर काम करने, उच्च स्तरीय संवाद की गति बनाए रखने, राजनीतिक आपसी विश्वास मजबूत करने, व्यावहारिक सहयोग बढ़ाने, मतभेदों को ठीक से संभालने और चीन-भारत संबंधों के स्थिर और स्वस्थ विकास को बढ़ावा देने के लिए तैयार हैं।"

उन्होंने कहा, "चीन और भारत दोनों प्रमुख विकासशील देश हैं और ग्लोबल साउथ के महत्वपूर्ण सदस्य हैं।

एक-दूसरे को सफलता की ओर ले जाने वाले साझेदारों के रूप में ड्रैगन और हाथी का सहयोगात्मक नृत्य दोनों पक्षों के लिए सही विकल्प है।"

भारत और चीन के बीच तनाव कम करने के प्रयासों में तेजी आई है, जबकि वाशिंगटन के साथ भारत के संबंध व्यापार विवादों के चलते तनावपूर्ण बने हुए हैं।

राष्ट्रदूत (एच.यू.एफ.) के लिए मुद्रक एवं प्रकाशक सोमेश शर्मा द्वारा वतन प्रेस, सुधर्मा, एम.आई.रोड़, जयपुर एवं सुधर्मा-II, लालकोठी शॉपिंग सेंटर, टोंक रोड़, जयपुर से मुद्रित एवं प्रकाशित। संपादकः- राजेश शर्मा । आर.एन.आई. नं. 3641/57, ई-मेल-rastrdut@gmail.com कोटा कार्यालयः-पलायथा हाउस, छत्रपति शिवाजी मार्ग, कोटा। फोन:2386031, 2386032, फैक्स:0744-2386033 बीकानेर कार्यालयः-कुंम्भाना हाउस, हनुमान हत्था, बीकानेर। फोन:2200660, फैक्स: 0151-2527371 उदयपुर कार्यालयः-आयड, मेन रोड आयड, उदयपुर। फोन: 2413092, 2418945, फैक्स: 0294-2410146 अजमेर कार्यालयः-घूघरा घाटी, जयपुर रोड,अजमेर। फोन: 2627612, फैक्स:0145-2624665 जालोर कार्यालय :- जी 1/63, इन्डस्ट्रीयल एरिया, फेस प्रथम, जालोर। फोन: 226422, 226423, फैक्स: 02973-226424 हिण्डौनसिटी कार्यालय :- जी -1-201, रीको औद्योगिक क्षेत्र, हिण्डौनसिटी। फोन: 230200, 230400, फैक्स: 07469-230600 चूरू कार्यालयः एच-150, रीको औद्योगिक क्षेत्र, चूरू, फोन: 256906, 256907, फैक्स:01562-256908